(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार तथा मिलों द्वारा अलग अलग कितना धन दिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां, शर्करा कारखानों के आसपास गन्ने की सघन खेती की एक योजना उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब राज्यों में कार्यान्वित करने के लिये हाल ही में हाथ में ली गई है।

(ख) एक शर्करा कारखाने के लिए इस योजना पर वार्षिक खर्च लगभग १.४४ लाख रुपया होगा और यह खर्च केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार और हितार्धिकारियों अर्थात् गन्ना उत्पादकों और शर्करा कारखानों में बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा।

खाद्यान्नों पर उर्वरक का प्रभाव

*६३१. **श्री ब० प्र० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक के प्रयोग द्वारा उत्पादित खाद्यान्न अस्वास्थ्यकर होता है ;

(ख) क्या विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). उर्वरकों की सहायता से पैदा हुए खाद्यान्नों से हानिकारक या लाभकारी प्रभावों को जानने के लिए चूहे जैसे जीवों पर परीक्षण करके भली भांति देखा जा सकता है। अभी तक इस प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। फिर भी भारतीय कृषि अनुसंधान विभिन्न प्रकार के खादों और उर्वरकों के खाद्यान्नों के पौष्टिक मूल्य और उसकी किस्म पर हुए प्रभावों को मालूम करने के लिए कुछ परीक्षण कर रहा है। इन परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि उर्वरकों के प्रयोग से खाद्यान्नों की किस्म पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके प्रतिकूल यह देखने में आया है कि नाईट्रोजन को अधिक मात्रा में देने से गेहूं और मक्का के दानों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है।

Berthing Facilities for Vessels at Minor Ports

*934. **Shri A. V. Raghavan:** Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to provide direct berthing facilities for vessels of eight to ten feet draft in selected minor ports;

(b) if so, whether the National Harbour Board has finalised the scheme; and

(c) the names of ports which have been selected for providing such facilities?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) Yes.

(b) No. The National Harbour Board at its meeting held at Kandla on the 11th and 12th November, 1963, appointed a sub-Committee under the Chairmanship of the Nautical Adviser to the Government of India to make a study of the minor ports, where alongside berthing facilities for vessels of eight to ten feet draft could be provided. Its report is awaited.

(c) Does not arise.